



Neutral Citation : 2026:AHC-LKO:21285

आरक्षित निर्णय

निर्णय सुरक्षित : 24.02.2026

निर्णय प्रदत्त : 25.03.2026

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ पीठ

ए.एफ.आर.

रिट-सी संख्या-704 वर्ष 2026

शहबान एवं अन्य

.....याचिकाकर्तागण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, अपर मुख्य सचिव (राजस्व), लखनऊ के माध्यम से एवं अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता : श्री अब्दुल हलीम, श्री आशिद अली, श्री मोहम्मद दानिश, श्री मोहम्मद काशिफ, श्री मोहम्मद मंसूर, श्री मोहम्मद शमीम खान

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता (सी.एस.सी.), श्री दिलीप कुमार पाण्डेय

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



न्यायालय संख्या – 5

माननीय न्यायमूर्ति आलोक माथुर

1. श्री मो. मंसूर, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता के साथ-साथ श्री योगेश कुमार अवस्थी, प्रतिवादियों के लिए विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना।
2. याचिकाकर्ता ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत कार्यवाही को चुनौती दी है, जिसके तहत बेदखली और जुर्माना लगाने का आदेश याचिकाकर्ता के खिलाफ अवैध रूप से अतिक्रमण करने और गाटा नंबर 648, क्षेत्र 0.300 हेक्टेयर में स्थित भूमि पर एक मस्जिद का निर्माण करने के लिए पारित किया गया है, जिसे राजस्व रिकॉर्ड में "खलिहान" के रूप में दर्ज किया गया है और परिणामस्वरूप यह ग्राम सभा से संबंधित भूमि है।
3. आरसी फॉर्म 19 में एक नोटिस जारी करके कार्यवाही शुरू की गई थी, जिसमें याचिकाकर्ताओं को कारण बताने की आवश्यकता थी कि उन्हें गाटा नंबर 648 पर स्थित भूमि से बेदखल क्यों नहीं किया जाना चाहिए, जो गांव अस्ती, परगना मोहना, तहसील – बखशी-का-तालाब, जिला – लखनऊ में स्थित है। नोटिस के अनुसरण में, याचिकाकर्ता 11/12/2024 को तहसीलदार के समक्ष पेश हुए थे और यह कहते हुए अपनी आपत्तियां दर्ज की थीं कि उन्होंने ग्राम सभा की भूमि पर मस्जिद का निर्माण नहीं किया था, और मौजूदा मस्जिद का निर्माण 60 साल पहले इस्लाम का पालन करने वाले व्यक्तियों की सुविधा के लिए किया गया था और नोटिस को रद्द करने के लिए प्रार्थना की थी।
4. तहसीलदार ने याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर विचार करने के बाद इसे खारिज कर दिया कि जिस भूमि पर गाटा संख्या 648 पर मस्जिद मौजूद थी, वह "खलिहान" के रूप में दर्ज की गई है और इसलिए यह ग्राम सभा के स्वामित्व वाली भूमि है, और याचिकाकर्ता का विवादित भूमि में कोई अधिकार या स्वामित्व नहीं है और इसलिए उसने 36000/- रुपये का जुर्माना लगाने और बेदखली के आदेश पारित किए।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



5. याचिकाकर्ताओं ने दिनांक 28/02/2025 के आदेश से व्यथित होकर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (न्यायिक) लखनऊ के समक्ष अपील की। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने रिकॉर्ड पर मौजूद पूरी सामग्री पर विचार करने के बाद यह विचार किया कि याचिकाकर्ता यह प्रदर्शित करने में सक्षम नहीं हैं कि विवादित संपत्ति में उसका कोई अधिकार, हित या शीर्षक है क्योंकि इसे निर्विवाद रूप से ग्राम सभा की भूमि के रूप में दर्ज किया गया था और तदनुसार तहसीलदार द्वारा पारित दिनांक 28/02/2025 के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिला और तदनुसार दिनांक के आदेश के माध्यम से अपील को खारिज कर दिया 31/10/2025.

6. इसके बाद, याचिकाकर्ताओं द्वारा तत्काल रिट याचिका दायर की जाती है, जिसमें दिनांक 28/02/2025 के आदेश की वैधता के साथ-साथ 31/10/2025 के अपीलीय आदेश की वैधता पर भी हमला किया जाता है।

7. याचिकाकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया गया है कि तहसीलदार द्वारा कानून के तहत निर्धारित प्रक्रिया का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि याचिकाकर्ता को सुनवाई के उचित अवसर से वंचित कर दिया गया था और लेखपाल का बयान कभी दर्ज नहीं किया गया था और न ही राज्य द्वारा कोई सबूत दिया गया था, न ही याचिकाकर्ताओं को राज्य के किसी भी गवाह से जिरह करने की अनुमति दी गई थी और इसलिए रिट याचिका में आक्षेपित के आदेश।

8. प्रस्तुत करने के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता, याचिकाकर्ताओं ने **ऋषिपाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, रिट-सी संख्या 6658/2022** के मामले में इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ के फैसले पर भरोसा किया है। यह जोरदार तर्क दिया गया था कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67 के तहत शक्ति का प्रयोग करते समय अधिकारियों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णय के पैराग्राफ 74 और 75 में स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है, जो इस प्रकार है: -

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



"74. इस प्रकार, मेरे विचार में, दिशानिर्देशों को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67, 67A और 26 के तहत कार्यवाही पर लागू होने वाली प्रक्रिया के रूप में अपनाया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य प्रक्रिया में पारदर्शिता, अधिकारियों द्वारा दृष्टिकोण में विवेकपूर्ण व्यवहार सुनिश्चित करना और लंबे समय से बसे हुए कब्जे को हटाने और एक निर्दोष ग्रामीण को अनावश्यक उत्पीड़न का कारण बनने के लिए गुप्त और तिरछे उद्देश्य से की गई हर शिकायत को विफल करना है:

(i) आरसी पर की गई शिकायत के मामले में 19 से, इसे बनाने वाला अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि इस निर्णय में की गई टिप्पणियों के आलोक में उचित सर्वेक्षण किया जाए; जिस भूमि पर कब्जा किया गया है, जिसे अनधिकृत माना गया है, सटीक माप में है और इसलिए भूमि राजस्व सर्वेक्षण विनियम, 1978 के अनुसार पैमाने पर तैयार किए गए सर्वेक्षण मानचित्र में भी दिखाया गया है; सर्किल रेट के आधार पर नुकसान का सही आकलन और उस आधार पर की गई गणना का विवरण।

(ii) स्वतः संज्ञान कार्रवाई के मामले में, आरसी फॉर्म 20 जारी करने से पहले, प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि आरसी फॉर्म 19 पर उचित रिपोर्ट उपनियम 1 नियम 67 के मापदंडों पर उपरोक्त पैरा (i) के अनुसार प्रस्तुत की जाए।

(iii) आरसी फॉर्म 20 के साथ आरसी फॉर्म 19 के साथ प्रस्तुत रिपोर्ट और स्पॉट सर्वे की एक प्रति उस व्यक्ति को होनी चाहिए, जिसके खिलाफ कार्यवाही शुरू की गई है, या यहां तक कि उपरोक्त पैरा (ii) के तहत स्वतः संज्ञान कार्रवाई के मामले में अन्यथा प्रस्तुत किया गया है।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(iv) नोटिस का उत्तर दायर किए जाने पर, यदि प्राधिकरण को पता चलता है कि स्थल सर्वेक्षण/स्पष्टीकरण रिपोर्ट संतोषजनक नहीं है, तो वह पीड़ित पक्षकार की उपस्थिति में एक नई स्पॉट रिपोर्ट तैयार करने का आदेश दे सकता है।

(v) यदि आपत्ति में धारा 67-क के अंतर्गत सांविधिक संरक्षण/लाभ की दलील शामिल है, तो प्राधिकरण को गांव सभा से आपत्ति आमंत्रित करनी चाहिए और धारा 67 के अधीन मामले के साथ-साथ उस पर निर्णय लेगा, जिसमें पीड़ित पक्ष को धारा 67-क के अंतर्गत अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(vi) यदि रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर स्वीकार किया जाता है, तो कोई आपत्ति दर्ज नहीं होने की स्थिति में हो सकता है, तो प्राधिकरण को अपने बयान से रिपोर्ट को साबित करने के लिए, पीड़ित पक्ष को उससे पूछताछ करने का अधिकार के साथ, उसके समक्ष रिपोर्ट तैयार करने वाले व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित करनी चाहिए।

(vii) प्राधिकरण को संबंधित अधिनियम और नियमों के तहत निर्धारित समय-सीमा के भीतर मामले पर निर्णय लेने का प्रयास करना चाहिए और नियमित तरीके से पक्षकारों को स्थगन देने से बचना चाहिए।

(viii) उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67(5) के अंतर्गत अंतरिम राहत आवेदन के साथ निर्धारित समय के भीतर दायर की गई अपील के मामले में, जहां तक संभव हो, अंतरिम राहत आवेदन पर दूसरे पक्ष को पूर्व सूचना के साथ दो सप्ताह के भीतर निर्णय लिया जाना चाहिए और जहां धारा 67-क के तहत निपटान की दलील सहायक कलेक्टर-प्रथम श्रेणी के समक्ष ली गई है, और कुल हर्जाने के कम से कम 25% तक के नुकसान का भुगतान किया जाता है और प्रश्नाधीन भूमि पर कोई और निर्माण नहीं करने के लिए वचन पत्र दायर किया जाता है, नागरिक प्रशासन सहित अधिकारियों को अंतरिम राहत आवेदन के निपटान तक अपील किए गए आदेश के अनुसार कोई भी

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



दंडात्मक उपाय करने से बचना चाहिए। अपीलीय प्राधिकारी स्थगन आवेदन के साथ अपील दायर करने के पहले दिन अंतरिम राहत देने पर भी विचार कर सकता है यदि अपीलकर्ता द्वारा उपरोक्त शर्तों को पूरा किया जाता है।

(ix) अपीलीय प्राधिकारी को जहां तक संभव हो, अपील प्रस्तुत करने के दो महीने की अवधि के भीतर निर्णय लेना चाहिए।

75. भारत बड़े पैमाने पर गांवों में रहता है और अभी भी कुल मिलाकर एक कृषि अर्थव्यवस्था है। उत्तर प्रदेश राज्य कोई अपवाद नहीं है। तदनुसार, मैं यहां देख सकता हूं कि प्रक्रिया के नियमों को राज्य सरकार द्वारा उपयुक्त रूप से संशोधित किए जाने के योग्य है, जिसमें उपरोक्त दिशानिर्देशों को शामिल किया जाना चाहिए, ताकि किसी भी मनमानी के लिए कोई गुंजाइश न छोड़ी जा सके, जिसे बड़े पैमाने पर प्राधिकरण द्वारा निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करने के रूप में देखा जाता है, स्थानीय गांव की राजनीति के लिए हो सकता है।

9. याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता श्री मोहम्मद मंसूर ने तर्क दिया कि उक्त निर्णय के पैराग्राफ 51 में, स्पष्ट शब्दों में, यह देखा गया है कि सहायक कलेक्टर द्वारा अवैध अतिक्रमण के बारे में निष्कर्ष पर तभी पहुंचा जा सकता है जब राज्य पक्ष के गवाहों की जांच की जाए और पीड़ित व्यक्ति द्वारा पेश किए गए गवाहों की भी जांच की जाए। पैराग्राफ 51 में, उक्त प्रक्रिया के औचित्य को समझाया गया था, जहां यह देखा गया था कि यदि गवाहों की परीक्षा और जिरह के आलोक में रिपोर्ट की सराहना करके उचित प्रक्रिया का पालन किया जाता है और संबंधित पक्षों द्वारा मौके पर निरीक्षण रिपोर्ट के साथ संबंधित पक्षों के नेतृत्व में सबूतों की उचित सराहना की जाती है, तो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67 के साथ पठित नियम 67 के उप-नियम 6 के तहत सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी द्वारा पारित आदेश एक ऐसा आदेश बनें जहां कोई कह सके कि न्याय न केवल किया गया है बल्कि किया गया है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



10. यह प्रस्तुत किया गया था कि गवाहों की परीक्षा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67 के तहत कार्यवाही की एक अनिवार्य विशेषता है, और जहां भी राजस्व अधिकारियों की जांच नहीं की जाती है या जिरह करने की अनुमति नहीं दी जाती है, या नोटिस के तहत व्यक्ति को साक्ष्य पेश करने की अनुमति नहीं दी जाती है, तो यह माना जाएगा कि उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है और पूरी कार्यवाही रद्द की जा सकती है। वर्तमान मामले में, यह प्रस्तुत किया गया था कि अपना जवाब प्रस्तुत करने के बाद ही, कार्यवाही समाप्त हो गई थी और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67 के तहत आदेश पारित किया गया था, जिसमें याचिकाकर्ताओं को ग्राम सभा की भूमि पर अवैध कब्जा घोषित किया गया था, और इस तरह की कार्यवाही ऋषिपाल सिंह (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के फैसले का स्पष्ट उल्लंघन है और इसलिए इसे रद्द किया जा सकता है।

11. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने रिट याचिका का विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमों के नियम 66 और 67 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67 के तहत कार्यवाही संक्षिप्त कार्यवाही है, और आगे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 225-क के अनुसार स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि न्यायालय के समक्ष किसी भी सारांश कार्यवाही में निर्धारण के लिए उत्पन्न होने वाले सभी प्रश्नों का निर्णय निर्धारित तरीके से हलफनामे पर किया जाएगा और केवल तभी जहां राजस्व न्यायालय या राजस्व अधिकारी संतुष्ट है कि हलफनामा दायर करने वाले किसी भी गवाह की जिरह आवश्यक है इस तरह की जिरह के लिए गवाह को पेश करने का निर्देश देगा। यह प्रस्तुत किया गया था कि राजस्व अधिकारियों के लिए इस तरह की कार्यवाही में बयान दर्ज करना अनिवार्य नहीं है, और जिरह भी की जानी चाहिए। उपयुक्त मामलों में, सहायक कलेक्टर, अपने विवेक से, ऐसी परीक्षा और जिरह की अनुमति दे सकता है, लेकिन यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



12. यह भी प्रस्तुत किया गया था कि **ऋषिपाल सिंह (उपरोक्त)** के मामले में इस न्यायालय ने केवल उस प्रक्रिया का प्रस्ताव दिया था जिसका उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67 के तहत कार्यवाही में पालन किया जाना चाहिए और इसलिए जैसा कि उक्त निर्णय के पैरा 74 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि दिशानिर्देशों को धारा 67 के तहत कार्यवाही पर लागू होने वाली प्रक्रिया के रूप में अपनाया जाना चाहिए, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के तहत 67क और 26 के तहत संशोधन किया गया है। उनके इस निवेदन को प्रचारित करने के लिए अपनाए गए शब्द पर बहुत जोर दिया गया था कि उक्त निर्णय में बताई गई प्रक्रिया से पहले मौजूदा नियमों को संशोधित करना होगा, जिसे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67 के तहत कार्यवाही में सार्वभौमिक रूप से लागू किया जा सकता है, और आज तक नियमों में संशोधन नहीं किया गया है, **ऋषिपाल सिंह (उपरोक्त)** के निर्णय में निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर आक्षेपित आदेशों का परीक्षण नहीं किया जा सकता है। अंत में, यह प्रस्तुत किया गया था कि जहां कानून स्वयं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67 के संबंध में सारांश कार्यवाही निर्धारित करता है, तो, मौजूदा प्रावधानों को रद्द किए बिना, नियमित कार्यवाही निर्धारित करने वाले नियमों का एक नया सेट निर्धारित नहीं किया जा सकता है, जो न्यायालय द्वारा राजस्व संहिता के नियमों के अनुसार नुस्खे के पूरी तरह से विपरीत हैं। जो कानून के बराबर होगा, जो अनुमेय है।

13. मैंने पार्टियों के प्रतिद्वंद्वी तर्कों को सुना है और रिकॉर्ड का अवलोकन किया है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67 के तहत कार्रवाई शुरू करने और जारी रखने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमों के नियम 66 और 67 में प्रदान की गई है। कार्यवाही की प्रकृति और इस संबंध में कानून की आवश्यकताओं के बारे में पता लगाने के लिए नियमों को उद्धृत करना फायदेमंद होगा: –

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



"66. धारा 67(1) द्वारा अपेक्षित सहायक कलेक्टर को सूचना अध्यक्ष या किसी सदस्य या भूमि प्रबंधन समिति के सचिव, या संबंधित स्थानीय प्राधिकरण के किसी अधिकारी द्वारा आरसी फॉर्म-19 में प्रस्तुत की जाएगी। 67 सहायक कलेक्टर द्वारा आगे की जांच (धारा 67) 67.

(1) नियम 66 के अधीन सूचना प्राप्त होने पर, या अन्यथा उसके ज्ञान में आने वाले तथ्यों पर, सहायक कलेक्टर ऐसी जांच कर सकेगा जो वह उचित समझे और निम्नलिखित बिंदुओं के संबंध में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकेगा: -

(क) गांव की संख्या, क्षेत्र, सीमा, क्षतिग्रस्त या दुवनियोजन की गई संपत्ति और उसके बाजार मूल्य के ब्यौरे के साथ हुए नुकसान या दुवनियोजन या गलत कब्जे का पूरा विवरण;

(ख) इस तरह की क्षति, दुवनियोजन या गलत कब्जे के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के माता-पिता के साथ पूरा पता;

(ग) गलत तरीके से कब्जे की अवधि, क्षति या दुवनियोजन और इसमें शामिल भूखंडों की मिट्टी का वर्ग; (घ) कलेक्टर द्वारा निर्धारित सर्कल रेट पर गणना की गई क्षतिग्रस्त या दुरुपयोग की गई संपत्ति का मूल्य और हजाने के रूप में वसूल की जाने वाली राशि।

(2) तत्पश्चात् सहायक कलेक्टर धारा 67(2) के अधीन कार्रवाई करने के लिए अग्रसर होगा और उस प्रयोजन के लिए आरसी प्रपत्र-20 में संबंधित व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस जारी करेगा कि नोटिस में विनिर्दिष्ट राशि से अधिक क्षति, दुवनियोजन या गलत कब्जे के लिए क्षतिपूर्ति उससे क्यों वसूल नहीं की जाए और उसे ऐसी भूमि से बेदखल क्यों न किया जाए।

(3) यदि धारा 67(2) में निर्दिष्ट नोटिस का अनुपालन नहीं किया जाता है या यदि संबंधित व्यक्ति द्वारा दिखाया गया कारण अपर्याप्त पाया जाता है, तो सहायक कलेक्टर आदेश द्वारा निर्देश दे सकेगा कि- क) ऐसे व्यक्ति

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



को ऐसे बल का प्रयोग करके बेदखल किया जाए जो आवश्यक हो; या (ख) सहायक कलेक्टर द्वारा आदिष्ट, क्षति अथवा गलत कब्जे के लिए मुआवजे की राशि, यदि विनिर्दिष्ट समय में भुगतान नहीं की जाती है, तो उप-नियम (3) में निर्दिष्ट व्यय की राशि सहित भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जा सकती है।

(4) वसूल किए जाने वाले नुकसान की राशि और आदेश के निष्पादन के व्यय को ऐसी सूचना में निर्दिष्ट किया जाएगा, जो निम्नलिखित तरीके से निर्धारित किया जाएगा: - क) क्षति या दुर्वनियोजन के मामले में, नुकसान की राशि का मूल्यांकन प्रचलित बाजार दर पर किया जाएगा। (ख) किसी भूमि पर अनधिकृत कब्जे के मामले में क्षति की राशि वह राशि होगी जो भूमि के बाजार मूल्य के पांच प्रतिशत के बराबर होगी, जिसकी गणना कलेक्टर द्वारा अनधिकृत कब्जे के प्रत्येक वर्ष के लिए निर्धारित सर्कल दर पर की गई है।

(ग) आदेश के निष्पादन के व्यय का मूल्यांकन प्रतिनियुक्त कर्मचारियों को देय एक दिन के वेतन और भत्तों के आधार पर किया जाएगा।

(5) यदि गलत तरीके से भूमि पर कब्जा करने वाले व्यक्ति ने उसमें खेती की है, तो उसे उस पर कब्जा रखने की अनुमति दी जा सकेगी जब तक कि वह फसल नहीं काट लेता, बशर्ते कि उसके द्वारा सकल दर के अनुसार परिकलित भूमि के बाजार मूल्य के पांच प्रतिशत के बराबर राशि का भुगतान न किया जाए, जिसे संचित गांव निधि या ग्राम पंचायत के अलावा अन्य स्थानीय प्राधिकरण की निधि में जमा किया जाएगा। मामला हो सकता है। यदि संबंधित व्यक्ति आरसी 40 फॉर्म-20 में नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के भीतर उपरोक्त राशि का भुगतान नहीं करता है, तो भूमि का कब्जा फसल के साथ, जैसा भी मामला हो, भूमि प्रबंधन समिति या स्थानीय प्राधिकरण को दिया जाएगा: बशर्ते कि जहां ऐसा व्यक्ति फिर से ग्राम पंचायत या स्थानीय के अधिकार क्षेत्र में उसी भूमि या किसी अन्य भूमि पर गलत तरीके से कब्जा कर लेता है प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, उसे वहां से तत्काल बेदखल कर दिया जाएगा और खाली

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



भूमि का कब्जा या उस पर फसल के साथ-साथ भूमि प्रबंधन समिति या स्थानीय प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, को सौंप दिया जाएगा।

(6) सहायक कलेक्टर कारण बताओ नोटिस जारी होने की तारीख से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर संहिता की धारा 67 के अधीन कार्यवाही को समाप्त करने का प्रयास करेगा और यदि ऐसी अवधि के भीतर कार्यवाही समाप्त नहीं होती है तो उसके कारण अभिलिखित किए जाएंगे।

(7) उपनियम (5) की कोई बात भूमि प्रबंधन समिति या स्थानीय प्राधिकारी को, जैसा भी मामला हो, उस व्यक्ति पर अभियोजन करने से विषिद्ध नहीं करेगी, जो भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 447 के अधीन संहिता या नियमों के अधीन बेदखल किए जाने के बावजूद दूसरी बार उसी भूमि पर अतिक्रमण करता है।

(8) प्रत्येक कलेक्टर के कार्यालय में आरसी फॉर्म-21 में एक रजिस्टर रखा जाएगा जिसमें धारा 67 के तहत कार्यवाही में दिए गए नुकसान और मुआवजे के कारण वसूली के लिए आदेशित राशि का विवरण दिखाया जाएगा।

(9) प्रत्येक तहसीलदार द्वारा एक समान रजिस्टर भी रखा जाएगा जिसमें ऐसी कार्यवाही में दिए गए नुकसान और मुआवजे की वसूली दिखाई जाएगी। तहसील में बनाए गए रजिस्टर में की गई प्रविष्टियों की तुलना कलेक्टर द्वारा बनाए गए रजिस्टर से की जाएगी ताकि उसमें की गई प्रविष्टियों की सटीकता सुनिश्चित की जा सके। (10) धारा 67 के अधीन कार्यवाहियों में दिए गए हर्जाने और दिए गए मुआवजे की वसूली को दर्शाने वाली प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष अप्रैल और अक्तूबर के पन्द्रहवें दिन तक राजस्व बोर्ड, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को भेजी जाएगी। बोर्ड जिलों से प्राप्त रिपोर्ट को समेकित करने के बाद इसे सरकार को भेजेगा। (11) नियम 66 और 67 की कोई बात किसी व्यक्ति को किसी ऐसे मामले के संबंध में जिसके लिए संहिता की धारा 67 के अधीन कोई आदेश दिया गया है, कानून के अनुसार सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय में अपने अधिकार, शीर्षक या हित की स्थापना से वंचित नहीं करेगा।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



14. राजस्व संहिता की धारा 67 के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया, गांव सभा की भूमि पर अतिक्रमण के बारे में सहायक कलेक्टर के संज्ञान में आने वाली जानकारी पर आधारित है, जो इसके बाद जांच करने के लिए आगे बढ़ सकता है और उस भूमि के विशेष क्षेत्र के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकता है जिस पर अतिक्रमण किया गया है, प्लॉट नंबर, संपत्ति की क्षेत्रफल सीमा और बाजार मूल्य। अतिक्रमण का पूरा विवरण प्राप्त करने के बाद, उस व्यक्ति को आरसी फॉर्म 20 में एक नोटिस जारी करना आवश्यक है, जिस पर कथित रूप से ग्राम सभा की भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। नोटिस के तहत रखे गए व्यक्ति को नोटिस का जवाब देने और अपनी आपत्तियां दर्ज करने का अधिकार है, और यदि वह नोटिस का जवाब नहीं देता है या उसकी प्रतिक्रिया अपर्याप्त या असंतोषजनक पाई जाती है, तो उक्त भूमि से बेदखली के लिए आदेश पारित किए जा सकते हैं, और गलत कब्जे के लिए नुकसान के लिए मुआवजा भी लगाया जा सकता है।

15. एक बार जब सहायक कलेक्टर द्वारा नियमों की धारा 67 (1) के तहत प्रदान की गई पूरी सामग्री प्राप्त हो जाती है, तो उसे आरसी फॉर्म 20 में उस व्यक्ति को नोटिस जारी करना होगा जिसने कथित रूप से ग्राम सभा की भूमि पर कब्जा कर लिया है। उक्त नोटिस में उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों का जवाब देने और खंडन करने का अधिकार है। उत्तर पर विचार करने पर, सहायक कलेक्टर को यह भी अनिवार्य किया जाता है कि वह यह निष्कर्ष निकालें कि उसका उत्तर अपर्याप्त पाया जाता है, तभी वह बेदखली के आदेश पारित कर सकता है और गलत कब्जे के लिए हर्जाना लगा सकता है।

16. यह संबंधित व्यक्ति के उत्तर पर विचार करने के चरण में, सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए, और सुनवाई के अनुसार और नोटिस में आरोपों का खंडन करने का पूरा अवसर देने के लिए, सहायक कलेक्टर द्वारा एक तर्कसंगत और बोलने का आदेश पारित किया जाना चाहिए, जिसमें स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया गया हो कि क्या

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



संबंधित व्यक्ति किसी अधिकार का प्रदर्शन करने में सक्षम है, विवादित संपत्ति में ब्याज या मालिकाना हक और तथ्य यह भी है कि विवादित भूमि ग्राम सभा के नाम पर दर्ज है या नहीं।

17. कार्यवाही की प्रकृति के संबंध में, यह देखा गया है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 225-क के अनुसार, यह प्रदान किया गया है कि कार्यवाही प्रकृति में सारांश होगी। धारा 225-क, इस प्रकार है: -

"225- क सारांश कार्यवाही में प्रश्नों का निर्धारण - इस संहिता के अन्य उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, इस संहिता के अधीन किसी भी संक्षिप्त कार्यवाही में निर्धारण के लिए उत्पन्न होने वाले सभी प्रश्नों का निर्णय शपथ पत्रों पर निर्धारित तरीके से किया जाएगा: परन्तु यदि राजस्व न्यायालय या राजस्व अधिकारी इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि किसी गवाह की जिरह आवश्यक है, जिसने शपथ पत्र दायर किया है, तो वह इस तरह की जिरह के लिए गवाह को पेश करने का निदेश दे सकता है।"

18. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमों के नियम 192 में प्रावधान है कि संहिता के तहत किसी भी सारांश कार्यवाही में निर्धारण के लिए उत्पन्न होने वाले सभी प्रश्नों का निर्णय हलफनामे पर किया जाएगा, और उप-नियम (2) घोषणा करता है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67 के तहत कार्यवाही को सारांश कार्यवाही के रूप में माना जाएगा।

19. तदनुसार, राजस्व संहिता की धारा 67 के तहत सांविधिक योजना के अनुसार, ग्राम सभा संपत्ति के नुकसान, दुवनियोजन और गलत कब्जे के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई के लिए प्रदान करते हुए, सहायक कलेक्टर ऐसी जानकारी प्राप्त करने पर और ग्राम सभा की संपत्ति को नुकसान, दुवनियोजन और गलत तरीके से नुकसान के बारे में संतुष्ट करने के बाद फॉर्म 20 में एक नोटिस जारी करेगा जिसमें पूरी जानकारी दी जाएगी। जिस व्यक्ति को नोटिस जारी किया गया है, उसके बाद उसे अपना बचाव प्रस्तुत करने का पूरा अवसर मिलेगा। सहायक कलेक्टर, इस स्तर पर, अपनी दलीलों के समर्थन में हलफनामे पर सभी सामग्री दाखिल कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



धारा 225 क के परंतुक के अनुसार, उसे किसी भी गवाह से जिरह करने की अनुमति दी जा सकती है जिसने हलफनामा दायर किया है।

20. वर्तमान मामले में, भूमि प्रबंधन समिति द्वारा सहायक कलेक्टर को फॉर्म 19 में जानकारी प्रस्तुत की गई थी, जिसमें कहा गया था कि याचिकाकर्ताओं ने लगभग 20 वर्षों की अवधि के लिए गांव – आस्ती, परगना मोहना, तहसील – बखशी का तालाब, जिला – लखनऊ में 0.300 हेक्टेयर क्षेत्र में गाटा नंबर 648 पर स्थित भूमि पर अतिक्रमण किया है। अतिक्रमण से संबंधित एक नक्शा भी संलग्न किया गया था। सहायक कलेक्टर द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर, याचिकाकर्ताओं को 21/10/2024 को फॉर्म 20 में नोटिस जारी किया गया, जिसमें उन्हें 11/11/2024 तक अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। याचिकाकर्ताओं ने 11/12/2024 को कारण बताओ नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया। इस बात से इनकार किया गया कि याचिकाकर्ताओं ने ग्राम सभा से संबंधित किसी भी भूमि पर अतिक्रमण किया था, और विवादित मस्जिद का निर्माण लगभग 60 साल पहले मुस्लिम समुदाय के सदस्यों द्वारा किया गया था। यह कहा गया था कि उन्हें उक्त मस्जिद के निर्माण से संबंधित तथ्यों की जानकारी नहीं थी, और कहा गया था कि गाटा नंबर 648, क्षेत्र 0.300 हेक्टेयर पर कोई अतिक्रमण नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने आगे इस बात से इनकार किया कि वे मस्जिद के प्रबंधन या उक्त मस्जिद के प्रबंधक/मुतवली का हिस्सा थे, लेकिन केवल नमाज के लिए मस्जिद गए थे।

21. तहसीलदार ने याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत उत्तर पर विधिवत विचार किया और पाया कि ग्राम-आस्ती, परगना मोहना, तहसील – बखशी का तालाब, जिला – लखनऊ में स्थित गाटा नंबर 648 में स्थित भूमि राजस्व रिकॉर्ड में खलिहान के रूप में दर्ज की गई थी और तदनुसार ग्राम सभा से संबंधित भूमि थी जिस पर मस्जिद का अवैध रूप से

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



निर्माण किया गया था और तदनुसार आदेश के माध्यम से बेदखली और जुर्माना लगाने के आदेश दिनांक 28/02/2025 पारित किए गए थे।

22. दिनांक 28/02/2025 के आदेश से व्यथित होकर, याचिकाकर्ताओं ने कलेक्टर, लखनऊ के समक्ष अपील की प्राथमिकता दी थी। चुनौती का मुख्य आधार यह था कि याचिकाकर्ताओं की आपत्तियों को तय करने में तहसीलदार द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया, जहां लेखपाल का बयान दर्ज नहीं किया गया था, न ही उसे तलब किया गया था, और याचिकाकर्ताओं को उससे जिरह करने का अवसर नहीं दिया गया था। कलेक्टर ने दिनांक 31/10/2025 के इस आदेश के माध्यम से अपील को खारिज कर दिया कि न तो ट्रायल कोर्ट के समक्ष और न ही अपीलीय न्यायालय के सामने, यह कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं का उक्त संपत्ति पर कोई अधिकार, हित या शीर्षक था जिसे खलिहान के रूप में दर्ज किया गया था और इसलिए यह ग्राम सभा से संबंधित भूमि थी और इसलिए, अपील में कोई दम नहीं पाया गया और तदनुसार इसे खारिज कर दिया।

23. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि उपरोक्त परिस्थितियों में तहसीलदार के समक्ष कार्यवाही स्पष्ट रूप से अवैध और मनमानी थी, क्योंकि लेखपाल का बयान कभी दर्ज नहीं किया गया था और न ही याचिकाकर्ताओं को उससे जिरह करने का कोई अवसर दिया गया था, जैसा कि ऋषिपाल (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय की समन्वय पीठ के निर्णय में प्रदान किया गया था और इसलिए प्रस्तुत किया गया था कि याचिका अनुमति दी जाए, और आक्षेपित आदेशों को रद्द किया जा सकता है और इस न्यायालय द्वारा बताई गई प्रक्रिया का पालन करने के बाद मामले को नए सिरे से निर्णय के लिए वापस भेज दिया जा सकता है।

24. हमने पक्षों के अधिवक्ता को सुना है और रिकॉर्ड का अवलोकन किया है। याचिकाकर्ता की दलीलें राजस्व संहिता की धारा 67 के तहत कार्यवाही में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के इर्द-गिर्द केंद्रित हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



नियमों के नियम 66 और 67 में निहित मौजूदा प्रक्रिया एक सारांश प्रक्रिया निर्धारित करती है, जबकि याचिकाकर्ता के अनुसार, इस न्यायालय ने ऋषिपाल के मामले में पालन करने के लिए एक विस्तृत नियमित प्रक्रिया निर्धारित की है, जिसमें मौखिक साक्ष्य का नेतृत्व और गवाहों की जिरह शामिल है।

25. जब उत्तर प्रदेश राजस्व न्यायालय नियमों के नियम 66 और 67 में निहित मौजूदा प्रावधानों की निहाई पर परीक्षण किया जाता है, तो हम पाते हैं कि जांच राजस्व अधिकारियों द्वारा की गई थी और उन्होंने फॉर्म 19 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें कानूनी अतिक्रमण के स्थान के संबंध में सभी आवश्यक सामग्री प्रदान की गई थी, जिसके अनुसार याचिकाकर्ताओं को फॉर्म 20 में नोटिस दिया गया था, इसमें अतिक्रमण की सीमा, अतिक्रमण का क्षेत्र आदि प्रदान करना और याचिकाकर्ताओं को अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहना है। उत्तर सहायक कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया था, जिन्होंने यह नहीं पाया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा गाटा संख्या 648 पर भूमि पर कब्जा करने के लिए कोई औचित्य दिया गया था, जो गांव – आस्ती, परगना मोहना, तहसील – बख्शी का तालाब, जिला – लखनऊ में स्थित था, जिसे खलिहान के रूप में दर्ज किया गया था और इसलिए एक ग्राम सभा भूमि थी। चूंकि याचिकाकर्ता यह प्रदर्शित करने में असमर्थ थे कि उक्त भूमि में उनका कोई अधिकार, शीर्षक या हित था, सहायक कलेक्टर ने माना कि उत्तर असंतोषजनक था और बेदखली और जुर्माना लगाने के आदेश पारित किए। तदनुसार, उपरोक्त सामग्री के अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादियों ने राजस्व संहिता नियमों के नियम 66 और 67 के तहत निर्धारित नियमों का पालन किया है, और यह नहीं कहा जा सकता है कि आक्षेपित आदेश उक्त नियमों का उल्लंघन करते हुए पारित किया गया था। जुर्माना लगाने के संबंध में, इस न्यायालय का विचार है कि याचिकाकर्ताओं को मस्जिद के निर्माण या कब्जे से जोड़ने के लिए कोई सामग्री नहीं थी, इसे बनाए नहीं रखा जा सकता है और तदनुसार इसे रद्द कर दिया जाता है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



26. याचिकाकर्ताओं के तर्क का दूसरा अंग, जिसकी यह न्यायालय जांच करने के लिए आगे बढ़ती है, ऋषिपाल (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा जारी निर्देशों के उल्लंघन के संबंध में है। उक्त निर्णय के पैराग्राफ 50 में, हम पाते हैं कि न्यायालय ने राज्य के लिए गवाहों की जांच और जिरह का प्रावधान किया है और राजस्व अधिकारियों द्वारा साक्ष्य का नेतृत्व किया है, जिन्होंने मौके के निरीक्षण के बाद अतिक्रमण के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ऋषिपाल (उपरोक्त) के पैराग्राफ 74 में, जहां उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67, 67 ए और 26 के तहत अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में निर्देश/दिशानिर्देश जारी किए गए हैं, हम पाते हैं कि ऋषिपाल (उपरोक्त) के निर्णय के पैरा 74 के खंड (vi) में, यह निम्नानुसार देखा गया है: -

"(vi) यदि रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर स्वीकार किया जाता है, तो शायद यदि कोई आपत्ति दर्ज नहीं की जाती है, तो प्राधिकरण रिपोर्ट तैयार करने वाले व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित करेगा, बयान द्वारा रिपोर्ट को साबित करने के लिए, पीड़ित पक्ष को उससे जिरह करने का अधिकार होगा।"

27. इसलिए, उक्त निर्णय के पैरा 74 में निहित पूर्वोक्त निर्देशों की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद, इस न्यायालय ने पाया कि निर्देशों का शेष भाग राजस्व संहिता नियमों के नियम 66 और 67 में पहले से निहित प्रावधानों का स्पष्टीकरण/प्रवर्धन है, लेकिन ऋषिपाल (उपरोक्त) के पैराग्राफ 74 के खंड (vi) में निर्धारित नियमों से प्रमुख विचलन प्रदान किया गया है, जिसके अनुसार यह प्राधिकरण के लिए अनिवार्य होगा रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति की जांच करना और उक्त प्राधिकारी को जिरह करने की अनुमति देना। मुद्दा यह है कि क्या ऋषिपाल (उपरोक्त) के पैरा 74 के खंड (vi) के उल्लंघन में जारी किए गए किसी भी आदेश को राज्य सरकार द्वारा उपयुक्त नियमों में संशोधन किए बिना रद्द किया जा सकता है?

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



28. यह कहना कठिन है कि वर्तमान परिस्थितियों में, विधानमंडल ने पहले ही ऐसे नियम तैयार कर लिए हैं जो राजस्व संहिता नियमों के नियम 66 और 67 में प्रदान किए गए हैं; यह ऐसा मामला नहीं है जहां उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67 के तहत कार्यवाही में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में किसी भी नुस्खे का अभाव है, जिससे न्यायालय शून्य को भरने के लिए कदम उठा सके। सर्वोच्च न्यायालय ने **विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य, 1997 (6) एससीसी 241** के मामले में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में दिशानिर्देश तैयार करने के लिए आगे बढ़े थे, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि घरेलू कानून के अभाव में, सभी कार्यस्थलों पर कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न की बुराई को रोकने के लिए प्रभावी उपाय तैयार करने के लिए। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष स्थिति को वर्तमान मामले के तथ्यों से स्पष्ट रूप से अलग किया जा सकता है, जहां विशिष्ट, वैध और लागू करने योग्य नियम मौजूद हैं; इसलिए, लागू करने योग्य दिशा-निर्देश तैयार करने की असाधारण शक्तियों का प्रयोग करने का कोई अवसर नहीं था जब तक कि मौजूदा नियमों को अधिकारातीत घोषित नहीं किया जाता है।

29. हम इस तथ्य पर भी ध्यान देते हैं कि **ऋषिपाल (उपरोक्त)** के मामले में इस न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमों में निर्धारित मौजूदा प्रक्रिया के साथ अपर्याप्तता या किसी भी कमजोरी पर चर्चा नहीं की है, बल्कि अपने आप में एक नए तंत्र का सुझाव दिया है और इसे धारा 67 के तहत प्रक्रिया के रूप में अपनाए जाने वाले दिशानिर्देशों के रूप में कहा है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के तहत 67क और 26 के तहत संशोधन किया गया है। एक बार जब न्यायालय ने स्वयं उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा उक्त दिशानिर्देशों/नियमों को अपनाने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं, तो इस तरह को अपनाना आवश्यक है, और इस तरह के अपनाने के बिना, इस न्यायालय द्वारा बनाए गए दिशानिर्देशों को लागू नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त के अलावा, हम पाते हैं कि यदि **ऋषिपाल (उपरोक्त)** के मामले में दिशानिर्देशों को अपनाया और लागू किया जाता है, तो प्रक्रिया, जो अब तक एक सारांश प्रक्रिया थी, को नियमित प्रक्रिया में

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



परिवर्तित किया जाएगा, जो पक्षों को साक्ष्य पेश करने का उचित अवसर दिए जाने के बाद ही निर्धारण के लिए प्रदान किया जाएगा। यह उपरोक्त कारण से है कि हमें नहीं लगता है कि राज्य द्वारा अपनाए जाने से पहले दिशानिर्देशों को लागू करने योग्य बनाने का कोई इरादा था, और नियमों में आवश्यक संशोधन किए गए थे, और इसलिए, यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67 के तहत कार्यवाही को मौजूदा प्रक्रिया के आधार पर आंका जाना होगा, **ऋषिपाल (उपरोक्त)** के मामले में बनाए गए दिशा-निर्देशों को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमों में संशोधन करके राज्य द्वारा अपनाए जाने तक।

30. उपरोक्त परिस्थितियों में, इस न्यायालय का विचार है कि राजस्व संहिता नियमों के नियम 66 और 67 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का वर्तमान मामले में पालन किया गया है, जबकि **ऋषिपाल (उपरोक्त)** के मामले में जारी दिशानिर्देशों का पालन करना अनिवार्य नहीं है, जब तक कि इसे उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा नहीं अपनाया जाता है।

31. तदनुसार रिट याचिका **खारिज** की जाती है।

(माननीय न्यायमूर्ति आलोक माथुर)

मार्च 25, 2026

ए. वर्मा

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”